मूल्य 1 रु.
वर्षः 14 - अंक : 104, मुंबई, शुक्रवार, 14 जून, 2024 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक
मुंबई हलचल
भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त ®
अब हर सच होगा उजागर

मराठा आरक्षण

मनोज जरांगे ने अनशन किया स्थगित

सरकार को दी एक महीने की मोहलत

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। दरअसल मराठा समुदाय को आरक्षण मिलने की मांग को लेकर मनोज जरांगे अंतरवाली सराती में 8 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। मनोज जरांगे पाटिल से सरकार के शिष्टमंडल मंडल ने मुलाकात की है।

शरद पवार से पहल करने की मांग

मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के अनशन और महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान नहीं लेने पर नासिक में मराठा समाज ने नाराजगी जताई थी। मराठा समाज ने मांग की थी कि शरद पवार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के संबंध में नासिक में संपूर्ण मराठा समाज की बैठक भी आयोजित हुई थी जिसमें शरद पवार से ध्यान देने की मांग की गई।

नागपुर की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट

5 लोगों की मौत, कई घायल

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। नागपुर शहर में एक विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में गुरुवार दोपहर को अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के दौरान कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। शुरूआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में से 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट की सूचना के बाद कई दमकल की गाड़ियां और एंबुलेंस मौके पर पहुंचे हैं और अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। नागपुर के धमाना इलाके में स्थित चामुंडी बारूद कंपनी में करीब डेढ़ बजे यह ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना तेज था कि आस-पास के कई इलाकों तक इसकी गूंज सुनाई दी है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

मुंबई में मिली गर्मी से राहत

कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है। दो दिन के बाद शुक्रवार को अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि शहर में जलभराव की स्थिति नहीं बनी। लोगों ने शानदार मौसम का आनंद उठाया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि गरज के साथ बारिश की शुरूआत हुई, लेकिन इससे शहर में कहीं भी बड़ी मात्रा में जलभराव की कोई खबर नहीं है। साथ ही रेलवे और बीईएसटी बस की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं काफी हद तक सामान्य ही रहीं। हालांकि कुछ स्थानों से सेवाओं में कुछ देरी देखने मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे में शहर और उपनगरों में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मुंबई में मॉनसून अपनी तारीख 11 जून से दो दिन पहले नौ जून को दस्तक दे चुका है।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पुणे पोर्शे हिट एंड रनः रईसजादे के दोस्तों का खुलासा

पब में पी थी 90 हजार रुपये की शराब

मुंबई हलचल/संवाददाता

मुंबई। पुणे के पोर्शे कांड को भला कौन भूल सकता है। पोर्शे कार चला रहे नाबालिग रईसजादे ने पिछले महीने बाइक सवार दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। इस कारण दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई थी। मामले में अभी भी जांच जारी है। इस बीच अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 18-19 मई की रात को नाबालिग आरोपी और उसके 15 दोस्तों ने दोनों पब में 90 हजार रुपये खर्च किए थे। नाबालिग आरोपी ने 48 हजार रुपये खर्च किए। जबकि, बाकी के 42 हजार रुपये उसके दोस्तों ने दिए। मामले में पुणे क्राइम ब्रांच ने नाबालिग के इन 15 दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

तीन अलग-अलग मामले दर्ज

मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में ससून जनरल अस्पताल के दो डॉक्टर और एक कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर नाबालिग के रक्त के नमूनों को उसकी मां के नमूनों से कथित तौर पर बदलने का आरोप है। पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में दुर्घटना के संबंध में एक प्राथमिकी और दूसरा मामला उस पब के खिलाफ है, जिसने कथित तौर पर नाबालिग को शराब परोसी थी। पुलिस ने लड़के के पिता पर बिना वैध लाइसेंस के उसे कार चलाने की अनुमति देने का मामला दर्ज किया है। तीसरा मामला परिवार के ड्राइवर को गलत तरीके से बंधक बनाने और जानलेवा दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने के लिए मजबूर करने से जुड़ा है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

शासन की निरंतरता और गठबंधन की मजबूरी

नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में शासन की निरंतरता जारी रखी है। केंद्र सरकार के सभी अहम मंत्रालयों में पुराने मंत्रियों की वापसी हुई है। राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा संभालते रहेंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा अमित शाह के पास ही रहेगा। अगर वे अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हैं तो यह एक रिकॉर्ड होगा क्योंकि देश में आज तक कोई भी नेता 10 साल तक गृह मंत्री नहीं रहा है। अर्थ नीति और विदेश नीति का जिम्मा क्रमशः निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के पास ही है और सड़क परिवहन व राजमार्ग का जिम्मा नितिन गडकरी के पास है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे चलाए रखने की जिम्मेदारी फिर से धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर डाली गई है। कुल मिला कर देश की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक नीतियों में कम से कम मंत्रियों के जरिए निरंतरता का संदेश दिया गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के आंकड़े बदलने और नई राजनीतिक स्थितियां पैदा होने से सरकारी की संरचना में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए निरंतरता बनाए रखने में मुश्किल होगी। लेकिन उन्होंने नई स्थितियों में भी शासन का पुराना ढांचा बनाए रखा है। अपने अपने विभागों में पुराने मंत्रियों की वापसी से यह संदेश गया है कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में नीतियों की जिस निरंतरता का वादा किया था उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ध्यान रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 10 साल में जो काम किया है वह ट्रेलर है पूरी फिल्म बाकी है। चुनाव प्रचार में उन्होंने एक रूपक का इस्तेमाल किया और कहा कि उनका अब तक का कामकाज स्टार्टर है, मेनकोर्स अभी बाकी है। अगर त्रिशंकु लोकसभा की वजह से सरकार की संरचना में बदलाव होता तो निश्चित रूप से उसका असर सरकार के कामकाज पर होता। उसकी नीतिगत और प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती। कह सकते हैं कि नई राजनीतिक स्थितियां उभरने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बाधा पार कर ली है। परंतु सवाल है कि क्या यह स्थिति स्थायी रहने वाली है या गठबंधन की मजबूरियां सरकार के कामकाज पर असर डालेंगी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि सहयोगी पार्टियों को उनकी संसदीय ताकत के हिसाब से कम मंत्री पद देने और अपेक्षाकृत कम महत्व के मंत्रालय देने का विरोध हुआ है। यह विरोध बहुत उग्र नहीं है फिर भी कई पार्टियों ने आपत्ति की है और दबी जुबान में ही सही विरोध प्रकट किया है। तभी उनके समर्थन और उनकी चुप्पी को सरकार फॉर गारंटेड नहीं ले सकती है। भले वे सरकार की स्थिरता के लिए खतरा पैदा नहीं करें लेकिन नीतिगत मसले पर सरकार को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं और अगर विपक्षी पार्टियां किसी मसले पर मजबूत विरोध दर्ज कराती हैं तो सहयोगी भी इस मौके का इस्तेमाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। यह स्थिति स्थायी रहने वाली है। विपक्षी पार्टियां भी सत्तारूढ़ गठबंधन की इस फॉल्टलाइन का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। यह सही है कि सरकार को संख्या के लिहाज से खतरा नहीं है लेकिन वह सहयोगी पार्टियों को एक सीमा से ज्यादा पीछे धकेलने की जोखिम नहीं ले सकती है। अगर सहयोगी पार्टियां जोर देकर कोई बात कहती हैं तो प्रधानमंत्री को उस पर ध्यान देना होगा।

समस्त मेमन जमात मालेगांव की जानिब से उर्दू घर मालेगांव में स्कूल, कोलेज के बच्चों की मोमेंटो देकर होंसला अफजाई की गई

मालेगांव में एक अच्छा स्कूल कॉलेज बनाएंगे : इकबाल मेमन ऑफीसर

मुंबई हलचल/शोएब म्यानुंर

मुंबई। नाशिक जिले के मालेगांव शहर में समस्त मेमन जमात मालेगांव की जानिब से उर्दू घर मालेगांव में तारीख 10 जुन 2024 को स्कुल, कोलेज के बच्चों की मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की गई। जिसमें तकरीबन 250 से अधिक बच्चों को उनकी पढ़ाई की महेनत को सारहना करते हुए मोमेंटो देकर हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मुख्य महेमानों में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफीसर, युथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रुटवाला, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर रविन्द्र जाधव, कांग्रेस प्रेसिडेंट एजाज बैग, राष्ट्र वादी कांग्रेस शरद पवार गट स्टेंडिंग कमेटी चैयरमेन सलिम अनवर, अब्दुल हलीम सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी सेक्रेटरी

मुस्तकीम डिगनेटी, समेत कई नामी गिरामी सख्सियात मौजूद रहे। इकबाल मेमन ऑफीसर ने एडयुकेशन पर रोशनी डाली और बताया कि इल्म हासिल करना जरूरी है मेमन समाज लेने वाला समाज है जो हर वक्त जरुरतमंदों के लिए हमेशा आगे आ कर मदद करती है मेमन लेने वाला नहीं देने वाला होना चाहिए। समस्त मेमन जमात मालेगांव की तरफ से इकबाल मेमन ऑफिसर को 'सालारे काफिला मेमन जमात' के खिताब से एवोर्ड देकर शानदार सम्मान किया गया। समस्त मेमन जमात मालेगांव की तरफ से प्रेसिडेंट शरीफ भाई मेमन जो हज के सफर पर होने से उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मदीना मुनव्वरा में दुआएं की। प्रोग्राम में समस्त मेमन जमात मालेगांव के वाईस प्रेसिडेंट बिलाल बावानी, प्रोटोगेंडा सेक्रेटरी साजीद भुरा, और पुरी युथ विंग ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।

कानपुर मेडिकल कॉलेज की पांचवी मंजिल से गिरकर महिला डॉक्टर की मौत, हिरासत में दो

परिजनों ने लगाया छत से फेंक कर हत्या का आरोप, इसीलिए दो साथी डॉक्टरों से भी पूछताछ कर रही पुलिस

मुंबई हलचल/संवाददाता

कानपुर। यहां के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में अचानक बड़ा हादसा हो गया। यहां की 5वीं मंजिल से गिरकर महिला डॉक्टर की मौत हो गई। यह घटना बीती देर रात उस समय की है, जब महिला डॉक्टर साथी डॉक्टरों के साथ पार्टी कर रही थी। बीती रात आयोजित पार्टी के लिए सभी डॉक्टर छत पर गए। थोड़ी देर में डॉक्टर दीक्षा तिवारी के छत से गिरने की आवाज आई। उसकी मौके पर मौत हो गई। साथी दोस्तों ने कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस, फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची और जांच-पड़ताल की। इस बीच मौके पर पहुंचे उसके परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जाने के चलते डा. दीक्षा तिवारी के दो साथी डाक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं साथी डॉक्टरों का कहना है- दीक्षा छत पर

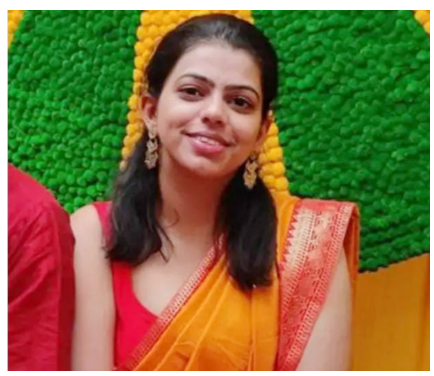

जिस जगह बैठी थी, वह जगह कमजोर थी। जिसके टूटने से वो नीचे गिर गई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर दीक्षा तिवारी के भाई ने कहा- छत पर रगड़ के निशान हैं। उसे छत से फेंका गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। इसी लिए पुलिस ने 2 साथी डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। साथ ही घटना की तह तक पहुंचाने के लिए सीसीटीवी भी चेक कर रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर दीक्षा तिवारी (26) बरेली की रहने वाली थी। और 2024 सेशन में ही उसने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। आगामी 25 जून को उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में जॉइनिंग लेनी थी। वह यहां स्वरूप नगर में किराए पर रहती थी। उनके पिता प्रदीप तिवारी का बरेली में प्रिंटिंग प्रेस का काम है। परिवार में मां रेनू तिवारी, भाई मयंक तिवारी हैं। मयंक पुणे में प्राइवेट नौकरी करते हैं। घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है वहीं पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की जांच कर रही है।

भारतीय मुक्ति मोर्चा बहुजन कर्मचारी संघ एवं प्रोफेसर टीचर नॉनटीचींग एमपलाई एसोसिएशन द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया: राम सुदिष्ट यादव जिला संरक्षक

मधुबनी। भारत मुक्ति मोर्चा ,भारतीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ(ट्रेड यूनियन)प्रोफेसर टीचर्स एंड नॉनटीचिंग एम्पलाई एसोसिएशन के द्वारा दिनांक 13 जून 2024 को विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। जिसकी अध्यक्षता भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ई. रंजीत कुमार ने किया अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यवस्था निजी धंधा नहीं है, बल्कि यह कार्य राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ है। लेकिन निजी एजेंसी के द्वारा शिक्षा विभाग को नियंत्रित एवं संचालित करना संविधान द्रोह का मामला बनता है। के के पाठक केशव कुमार पाठक जी संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। रामसुदिष्ट यादव जिला संरक्षक एवं विजय कुमार ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अपर मुख्य सचिव श्री के के पाठक एवं निजी एजेंसी के द्वारा निर्माण एवं साधन संसाधन के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग कर रहा है। वह निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन कराया जा रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए कमलेश पासवान भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला अध्यक्ष और मान्यवर संजय दास अधिवक्ता संघ प्रदेश प्रभारी ने कहा कि शिक्षक देहारी मजदूर नहीं है। शिक्षकों से निर्धारित समय से ज्यादा अवधि तक काम करवाया जा रहा है शिक्षक पेशा राष्ट्रीय सेवा का पेशा है लेकिन इसके साथ कोल्हू के बैल या बंन्धुआ मजदूर की तरह किया जाता है जो बिल्कुल अन्याय है इस कार्यक्रम में महिला संघ के जिला सदस्य पूजा कुमारी, ललिता देवी, राम प्रकाश राम, सुमन ठाकुर, शत्रुघन राम, अमर बिहारी, चंद्रशेखर दास, लक्ष्मी राम, मोहम्मद मुमताज आलम, श्याम बिहारी प्रमोद राम विकास कुमार नीलांबर, गणेश ठाकुर, भिखारी ठाकुर राजेश कुमार, गंगाराम, सुरेश पासवान सुबोध कामत, संजय राम आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

मालिक,मुद्रक,प्रकाशक–**दिलशाद एस खान** द्वारा एस आर प्रिंटिंग प्रेस,मोहन अर्जुन कंपाउंड, वैशाली नगर दहिसर (पूर्व),मुंबई–68 से मुद्रित व मुंबई हलचल,साईं मंगल को ऑ हॉ सो बी–2–301,इस्माइल बाग नियर मालाड शॉपिंग सेंटर, एस वी रोड,मालाड (प) मुंबई से प्रकाशित RNI NO MAHHIN/2010/34146, फोन: **9619102478 /9821238815**
email: mumbaihalchal@gmail com संपादक: **दिलशाद एस खान**, समाचार पत्र में छपे किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा न्याय क्षेत्र मुंबई होगा।

मनपा आयुक्त का अनोखा स्वागत

राकांपा ने भेंट किया समस्याओं को ज्ञापन

मुंबई हलचल/संवाददाता

जलगांव। मनपा आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे ने हाल ही में जलगांव मनपा आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने शहर की समस्याओं के बारे में ज्ञापन देकर उनका अनोखा स्वागत किया है। शरद पवार गुट के महानगर अध्यक्ष अशोक लाडवंजारी के नेतृत्व में उन्हें एक ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि जलगांव शहर में पानी की सप्लाई गड़बड़ा गई है। अमृत

योजना के तहत भी पूरे दबाव से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। साथ ही शहर में सफाई का एकाधिकार दिया गया है, लेकिन इस एकाधिकार से सफाई नहीं होती। इससे नागरिक नाराज हैं। शहर में कंक्रीट की सड़कें बनाने का काम चल रहा है। लेकिन ठेकेदार निचले दर्जे की खडी का उपयोग कर रहा है, इसलिए सड़कें गड्ढेदार हो गई हैं। इसके चलते इन सड़कों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि कमिश्नर होने के नाते उन्हें तुरंत इस समस्या पर ध्यान देना होगा और इसका समाधान करना होगा। वक्तव्य देते समय रिंकू चौधरी, सुनील माली, किरण राजपूत, हितेश जावले, सुहास चौधरी, रिजवान खटीक आदि मौजूद थे।

रोगमुक्त जीवन के लिए रक्तदान जरूरी : मुकुंद गौस्वामी

विकलांगता के बावजूद भी रक्तदान करने में नही रहते पीछे

मुंबई हलचल/संवाददाता

जलगांव। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है और कुछ गलत धारणाएं हैं कि हमें दान करने में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, लेकिन भगवान ने हमें एक अनमोल शरीर दिया है और हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने पर भी शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं। उक्त बातें समाजसेवी मुकुंद गौस्वामी ने रक्तदान करते हुए एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास नहीं है उस पर पछतावा करने के बजाय जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर हम दूसरों की अधिक आसानी से मदद कर सकते हैं। पोलियो रोग के कारण मुझमें 70% शारीरिक विकलांगता है और आज इस रोग के बावजूद भी मैं स्वतःस्फूर्त, स्वेच्छा से 100 से अधिक बार रक्तदान करने में सक्षम हुआ हूँ, कई बार मैंने श्वेत कोशिकाएँ (प्लेटलेट्स) भी दान किया है। रक्तदान के कारण आज मुझे कोई शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि मन

खुशी और ऊर्जा से भरा है। 18 वर्ष की आयु के बाद 50 किलो से अधिक वजन वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से रक्तदान कर सकता है, रक्तदान करने में बहुत कम समय लगता है। रक्तदान करने में कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है, एक ही रक्तदान आधुनिकता के कारण कई प्रकार के घटकों का निर्माण कर सकता है। तकनीक, रक्तदान करने के बाद किसी स्वस्थ आहार की आवश्यकता नहीं होती। आप जो नियमित रूप से भोजन करते हैं वह भी संभव है, जो रक्त हम देते हैं वह कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। हमारे शरीर में लगभग छह से सात लीटर रक्त होता है, जिसमें से केवल साढ़े तीन सौ मि.ली. यानी आधा लीटर तक रक्त हम दान करते हैं, प्रकृति ने आम आदमी को भी रक्त दान करने का बड़ा सौभाग्य दिया है, रक्त अभी भी किसी भी तरह से कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता है, रक्त की आवश्यकता केवल मनुष्य से ही पूरी की जा सकती है रक्त, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों, गर्भवती महिलाओं, एनीमिया से पीड़ित माताओं एवं बहनों को सदैव स्वस्थ रक्त की आवश्यकता होती है, हम सभी को स्वस्फूर्त रक्त दान करना चाहिए। अंततः रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है। जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।

(पृष्ठ 1 का समाचार)

मुंबई में मिली गर्मी से राहत

हालांकि पिछले दो दिनों में यहां बारिश नहीं होने की वजह से मौसम उमस भरा रहा था। हालांकि शुक्रवार सुबह हुई बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बता दें कि दो दिन पहले शहर में हुई बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस दौरान 150 एमएम से अधिक बरसात दर्ज की गई थी। जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अब तक इन इलाकों में मानसून नहीं आया है, जिसकी वजह से गर्मी काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 15 जून तक लू चलने की जानकारी दी है। जबकि प्रदेश में 24 जून तक मानसून आने की संभावना है।

नागपुर की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट

ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जिसका धुंआ कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। स्थानीय लोगों ने ब्लास्ट की सूचना दमकल को दी जिसके बाद आनन-फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू चलाकर अभी तक कुछ झुलसे हुए मजदूरों का बाहर निकाला है जिन्हे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। करीब 2 घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी दमकल की गाड़ियों मौके पर हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। जब फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उस वक्त कई मजदूर अंदर ही मौजूद थे जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। मृतकों में भी 4 महिलाएं बताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। राहत टीम के मुताबिक यह हादसा इतना बड़ा था कि धमाके से इमारत की छत तक डैमेज हो गई है ढील की है।

पुणे पोर्शे हिट एंड रन

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने 17 साल के नाबालिग की रिमांड होम 25 जून तक बढ़ाई है। वह 12 जून तक निगरानी गृह में रिमांड पर था। पुणे पुलिस ने अभियोजकों के माध्यम से नाबालिग की सुरक्षा का हवाला देते हुए निगरानी गृह में उसकी हिरासत अवधि को 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने बोर्ड को यह भी बताया कि वर्तमान समय में नाबालिग की रिहाई से मामले की चल रही जांच और 19 मई की दुर्घटना के बाद लिए गए उसके रक्त के नमूनों की कथित अदला-बदली समेत अन्य संबंधित मामलों में बाधा आ सकती है। बचाव पक्ष ने पुणे पुलिस की रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध किया और बोर्ड से कहा कि नाबालिग को निगरानी गृह से रिहा किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेजेबी ने नाबालिग की 25 जून तक निगरानी गृह में रहने की अवधि बढ़ा दी।

मराठा आरक्षण

जिसमें संदीपान भूमरे, संभुराजे देसाई शामिल थे। अनशन उन्होंने ऐसे वक्त में स्थगित किया है जब कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मनोज जरांगे ने 8 जून को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। अंतरवाली सराती में तैनात डॉक्टरों की एक टीम ने उनसे इलाज कराने का अनुरोध किया था। हालांकि, मनोज जरांगे पाटिल ने इलाज कराने से इनकार कर दिया है। अनशन स्थगित करने के बाद मनोज जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है।

बिजली सप्लाई खंडित, शिवसेना का आंदोलन

धुलिया। धुले शहर में बिजली वितरण कंपनी द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा बहुत खराब गुणवत्ता की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, वे बिजली बिल वसूल रहे हैं और खंडित बिजली के बदले में अपने ग्राहकों से कई अधिभार भी वसूल रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के तहत प्रदान की जाने वाली सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आती है और यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि अपने ग्राहकों को उनके भुगतान के लिए सही सेवा प्रदान करें। धुलिया शहर में पिछले कई वर्षों से चाहे मानसून हो या गर्मी, बिजली आपूर्ति अक्सर बाधित होती रही है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी होती है। दरअसल, इस संबंध में कई संगठन और पार्टियां कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन बिजली वितरण कंपनी प्रशासन अब तक नहीं जागा है। विद्युत वितरण कंपनी के आला अधिकारी समय पर कार्य पूरा दिखा कर सिर्फ खानापूरी कर रहे हैं। इस संबंध में पूरे धुलिया शहर में बिजली वितरण प्रणाली का अध्ययन करने के बाद शिवसेना की ओर से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं और हमने अनुरोध किया है कि हमें उन्हें तुरंत लागू करना होगा और उचित कदम उठाना होगा ताकि धुलिया शहर में बिजली की आपूर्ति सुचारू एवं निर्बाध हो सके।

1) पिछले 40 से 50 वर्षों से बिजली के जर्जर तारों को नहीं बदला गया है इसलिए वे बार-बार टूटते हैं और इन तारों से बिजली का रिसाव भी होता है, पूरे तार बदले जाएं।

2) पूरे धुलिया शहर में प्रमुख सड़कों पर बिजली के तारों को भूमिगत किया जाना चाहिए।

3) बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगाए गए खंभों का वजन 110 किलोग्राम तक होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ठेकेदार 70 से 75 किलोग्राम वजन वाले पोल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कई जगहों पर खंभे झुके हुए हैं, आज भी धुलिया शहर में ऐसे झुके हुए खंभे हैं जिससे तार टूटते हैं और विद्युत आपूर्ति बाधित होती है ऐसे खंभों को तत्काल बदला जाए।

4) शहर में कई डीपी में अनुशंसित कंपनी के फ़्यूज नहीं लगे हैं, जहां जुगलिंग तारों से बने फ़्यूज का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये तार बिजली के दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति में भी बाधा आती है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी के फ़्यूज लगाए जाते हैं। सभी डीपी पर स्थापित किया जाना चाहिए।

5) अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे राज्य सरकार को संपूर्ण बिजली वितरण प्रणाली को सुचारू करने के लिए आवश्यक राशि की एक रिपोर्ट तैयार करें और अपनी योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत करें और युद्ध स्तर पर संपूर्ण कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए सरकार से धन प्राप्त करें।

6) बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद बिजली वितरण कंपनी के वायरमैन रात में मरम्मत करने जाते हैं, उन्हें सही प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक टूल किट, झूला, दस्ताने जैसे विद्युत उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

7) शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली वितरण कंपनी के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतें बढ़ गई हैं और शिकायत पंजीकरण प्रणाली में जल्द से जल्द सुधार किया जाना चाहिए।

यदि निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर योजना बनाएं तो धुलिया शहर में संपूर्ण बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को गुप्त रूप से काम किए बिना स्थायी समाधान की योजना बनाने के लिए पूरे शहर में बिजली वितरण का गहन अध्ययन करना चाहिए। शिवसेना जिला प्रमुख अतुल सोनवणे, प्रोफेसर शरद पाटिल, किरण जोंधले धीरज पाटिल, डॉ. सुशील महाजन, भरत मोरे, ललित माली, मछिंद्र निकम, कैलास मराठे, शिवाजी शिरसाले, सुनील चौधरी, अमजद पठान, कपिल लिंगायत, शरद गोसावी, भटू गवली, दिनेश पाटिल, सागर निकम, अमोल ठाकुर, विष्णु जावड़ेकर, हर्षल वाणी, विक्की चौधरी, तेजस सपकाल और अन्य उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में संभाला अपना कार्यभार

आधुनिक हथियारों से लैस सशस्त्र सेनाएं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं: राजनाथ सिंह

पहली बैठक में रक्षा मंत्री ने की 100 दिन की कार्य योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिया क्रियान्वयन का निर्देश

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

चीन के साथ जारी एलएसी विवाद और पाकिस्तान की ओर से जम्मू क्षेत्र में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राजधानी के साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय में लगातार दूसरी बार देश के रक्षा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला।

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों, प्लेटफार्म से लैस किया जा रहा है। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। नई सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, नई प्रौद्योगिकी में नवाचार, सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, रक्षा निर्यात बढ़ाने व पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। रक्षा मंत्री ने वीरता और प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सैन्य कर्मियों की सराहना की।

आज विशाखापट्टनम जाएंगे राजनाथ

रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद रक्षा समीकरण में हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी पहली यात्रा के तौर पर 14 जून को नौसेना की विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी कमांड के मुख्यालय का दौरा करने का निर्णय लिया है। यहां वह अधिकारियों और नाविकों से बातचीत करेंगे।

50 हजार करोड़ का रक्षा निर्यात का लक्ष्य

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2028-29 तक 50 हजार करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2023-24 में ये आंकड़ा रिकॉर्ड 21 हजार 83 करोड़ पर पहुंच गया था। जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय के 100 दिनों की कार्य योजना पर एक समीक्षा बैठक भी हुई। जिसके केंद्र में पूर्व सैनिकों के कल्याण का बिंदु रहा। बैठक में राजनाथ ने सभी समर्पण के साथ अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने तथा योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। तेज प्रगति सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार समीक्षा बैठकें करेंगे।

सुबह 12 बजे संभाला कार्यभार

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 13 जनवरी की सुबह 12 बजे रक्षा मंत्रालय के प्रवेश द्वार संख्या-11 पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाप्रमुखों (जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर.चौधरी, नौसेनाप्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी) और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. समीर.वी कामत, सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) डॉ. नितेन चंद्रा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय के कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने भी मंत्रालय में रक्षा मंत्री से शिष्टाचार भेंट की। गौरतलब है कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शपथ गठन समारोह के बाद 12 जून को ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी के पहले सरकार गठन समारोह में शिरकत करने की वजह से राजनाथ सिंह ने 13 जून को रक्षा मंत्रालय में कार्यभार संभाला।

देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार : सरकार

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

- फिलहाल आयात शुल्क में बदलाव की कोई योजना नहीं
- बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त भंडार

सरकार ने कहा है कि देश के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने, कीमतों को स्थिर रखने के लिए और दयदि जरूरी हो, तो बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी उसका इन अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। विभाग ने बृहस्पतिवार को बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेईमान तत्वों द्वारा कोई जमाखोरी न हो और कीमतें स्थिर रहे, आवश्यकतानुसार उचित हस्तक्षेप किया जाएगा।' रबी विपणन सत्र वर्ष 2024 के दौरान विभाग ने 11.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन की जानकारी दी है। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 11 जून तक करीब 2.66 करोड़ टन अनाज खरीदा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा।

तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया

तिमाही बफर स्टॉक साल भर अलग-अलग होता हैं। एक जनवरी, 2024 तक, गेहूं का स्टॉक 1.38 करोड़ टन के निर्धारित बफर मानदंड के मुकाबले एक करोड़ 63.5 लाख टन था। बयान में कहा गया है, 'गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया है। इसके अलावा, वर्तमान में, गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।'

शीर्ष अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा-

हमारे पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं, दिल्ली जल संकट को 'जल्द' सुलझाएं

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल संकट विवाद से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे गुरुवार शाम पांच बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड के समक्ष अपनी मांग रखे। बता दें कि दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली सरकार ने आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है।

दिल्ली ने दायर किया हलफनामा

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अदालत इस मामले में हरियाणा से पूछे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल, कल 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।

बोर्ड को दिया निर्देश: कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार का आवेदन मिलने के बाद कल शाम बैठक कर इस मामले को जितना जल्द हो सके सुलझाएं।

चीन-पाक के संयुक्त बयान में कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर भारत पर की दो टूक

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

चीन और पाकिस्तान द्वारा हालिया जारी किए गए संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इन पर किसी तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह संयुक्त बयान बीते 7 जून को बीजिंग द्वारा चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया द्वारा इस बयान का लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली इस संयुक्त बयान में तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत आने वाली परियोजनाओं की भी निंदा करती है। साथ ही कहा कि उक्त भूभाग पर इस्लामाबाद द्वारा किए गए अवैध दावे को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। इस मामले को लेकर हमारी स्थिति दृढ़ता के साथ कायम है और इसके बारे में दोनों पक्ष (चीन और पाकिस्तान) भी पूरी तरह से अवगत हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा बने रहेंगे।

यूएन चार्टर के राग को भारत ने किया खारिज

चीन-पाक के संयुक्त बयान के मुताबिक, बीजिंग की वार्ता के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू-कश्मीर के मौजूदा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी। चीन के पक्ष की तरफ से यह दोहराया गया कि जम्मू-कश्मीर के विवाद को इतिहास के नजरिए से देखते हुए इसका समाधान यूएन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से निकाला जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त बयान में किए गए सीपीईसी के जिक्र का भी कड़े अंदाज में खंडन करते हुए कहा कि इसके तहत जारी परियोजनाएं भारत के संप्रभु भूभाग पर जारी हैं। यह वो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन अवैध ढंग से कब्जा किया हुआ है। ऐसे में हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में किसी भी अन्य देश द्वारा पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को लेकर दिए गए बयान या किसी भी टिप्पणी को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

ट्रक ने ऑटो को रौंदा, पांच लोगों की हो गई मौत

झारखंड के गढ़वा जिले के नगरऊंटारी में भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हादसा गढ़वा-डाल्टनगंज रोड पर पाल्हे नामक गांव के पास तब हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे सवारियों से लदे ऑटो को रौंद डाला। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार सभी लोग मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे थे। उन्हें नगरऊंटारी रेलवे स्टेशन से शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी। हादसे में पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी पहचान बिमलेश कुमार कनौजिया, अरुण भुइयां, बिकेश भुइयां, राजा कुमार और राजकुमार भुइयां के रूप में हुई है। वे नगरऊंटारी थाना क्षेत्र के सीरिया तोमर गांव के रहने वाले थे। उनके अलावा आठ लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। टक्कर के बाद घायलों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग सहायता के लिए दौड़े। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में राम प्रसाद राम, छोटू लाला भुइयां, उमेश भुइयां, राकेश भुइयां, मेराज अंसारी और संजय भुइयां शामिल हैं।

शांति से मनाई जाये ईद उल अजहा : मौलाना अदनान रजा

कुर्बानी के स्थानो और पशु बाजारों व्यपारियों की हो सुरक्षा, आरएसी ने दिया ज्ञापन

बरेली। ईद-उल-अजहा यानि बकराईद का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। बरेली सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रजा एक्शन कमेटी के लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पर जमा होकर ईद उल अजहा से सम्बंदित व्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। बरेली सहित पूरे प्रदेश के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में ईद-उल-अजहा का त्योहार सुख-शांति के साथ मनाये जाने मांग की कुरबानी के स्थलों और खरीदारी के लिए लगने वाले जानवरो के बाजारो की सुरक्षा की भी मांगी की।

पशु व्यापारियों और खरीदारों की सुरक्षा

प्रदेश भर में हजारों लोग साल भर जानवर पालकर बकरईद के मौके पर बाजार में बेचने लाते हैं। इसी से उनके परिवार का पालन-पोषण होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पशुओं को बाजार तक लाने में उन्हें किसी व्यवधान या असुरक्षा का सामना न करना पड़े। इसके लिए पशु व्यापारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रास्ते में जगह-जगह पुलिस मुस्तैद रहे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पशु बाजार तक आने में व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। इसके

साथ-साथ जानवर खरीदने वालों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए। पशु बाजारों और आसपास के क्षेत्रों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि असामाजिक तत्व व्यापार और त्योहार में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें।

कुर्बानी के स्थानों की सुरक्षा

जनता को उसकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रखने के लिए सभी पुलिस चौकियों तथा थानों को निर्दश दिए जाएं ताकि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर उचित प्रबंध कर लिए जाएं। सभी क्षेत्रों के सम्मानित नागरिकों से वार्ता कर क्षेत्र के हालात का जायजा लिया जाए और उसी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि कुर्बानी के स्थानों पर कोई अव्यवस्था न होने पाए।

कुर्बानी करने वालों की सुरक्षा

आम लोग अपने हाथ से कुर्बानी नहीं करते इसलिए कुर्बानी करने वालों के आने-जाने में व्यवधान से बचने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आम जुबान में जिसे हिस्से वाली कुर्बानी कहा जाता है उसके लिए भी उचित व्यवस्था की जाए।

ईदगाह मस्जिदों के आसपास सुरक्षा तथा साफ-सफाई

ईदगाह, मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश जारी किए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ईदगाह, मस्जिदों के आसपास सफाई का भी खास ध्यान रखा जाए।

पानी सप्लाई सुचारू रखी जाए

इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली सप्लाई में बाधा आ रही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं इसलिए बिजली की जबरदस्त कटौती बंद होनी चाहिए। बरेली को स्मार्ट सिटी सहित कई नाम दिए जा रहे है मगर पूरे जिले को अंधेरे में झोक दिया गया है। इतनी जबरदस्त कटौती पिछली हुकूमतों के समय भी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। भीषण गर्मी और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में बिजली न मिलने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ईद-उल-अजहा के तीनों दिन बिजली सप्लाई सुचारू रखी जाए, साथ ही पानी की सप्लाई भी सुचारू रखने की व्यवस्था की जाए।

वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक

जीएसटी परिषद की बैठक 22 जून को गेमिंग पर कर की समीक्षा की संभावना

मुंबई हलचल / नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 22 जून को होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर 28 प्रतिशत जीएसटी के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सकती है।

जीएसटी परिषद सचिवालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ' जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नयी दिल्ली में होगी। परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे।

चुनाव के बाद परिषद की पहली बैठक

बैठक के एजेंडा की जानकारी अभी परिषद के सदस्यों को नहीं दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद यह परिषद की पहली बैठक होगी। जीएसटी परिषद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले की समीक्षा कर सकती है। यह कर एक अक्टूबर, 2023 से लागू हुआ था।

गेमिंग पर किए गए मूल्यांकन की समीक्षा जरूरी

हालिया मुकदमों के कारण विभिन्न दर-संबंधी स्पष्टीकरण भी अपेक्षित हैं। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के भागीदार रजत बोस ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और अक्टूबर, 2023 में पेश किए गए मूल्यांकन नियमों की समीक्षा जैसे प्रमुख उद्योग मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है।

- गेमिंग क्षेत्र में 28 फीसदी जीएसटी की समीक्षा संभव
- परिषद की 53वीं बैठक 22 जून को नई दिल्ली में
- बैठक के एजेंडा की जानकारी अभी सदस्यों को नहीं दी गई

उपकर भी लगाया जाता है

जीएसटी परिषद अपनी 22 जून की बैठक में प्रक्रिया को तेज करने और समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का निर्णय ले सकती है। जीएसटी व्यवस्था में वर्तमान में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के पांच कर स्लैब हैं। विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर उच्चतम 28 प्रतिशत कर दर के अलावा उपकर भी लगाया जाता है।

दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत

डेलॉयट इंडिया की भागीदार एम एस मणि ने कहा कि परिषद को बहुप्रतीक्षित दरों को तर्कसंगत बनाने की चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा, '' इसके अलावा, प्राकृतिक गैस जैसे कम प्रभाव वाले पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने का प्रारंभिक प्रयास व्यवसाय के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा।''

पूरे दांव मूल्य पर 28 फीसदी कर लगेगा

जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को कर योग्य दावों (बेट) के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी। साथ ही स्पष्ट किया था कि ऐसी आपूर्तियों के मामले में पूरे दांव मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।

अप्रैल के बाद से कोई बैठक नहीं हुई

उस समय कहा गया था कि कार्यान्वयन की समीक्षा छह महीने बाद यानी अप्रैल, 2024 में की जाएगी। चूंकि अप्रैल के बाद से जीएसटी परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए परिषद की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कराधान की समीक्षा की उम्मीद है।

कर देयता पर विचार जारी

केपीएमजी इन इंडिया के साझेदार एवं प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि अक्टूबर से पहले ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए कर देयता, ईएसओपी की कर देयता, कॉरपोरेट गारंटी कर देयता सहित कई स्पष्टीकरणों पर विचार किया जा रहा है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

छिलकों के साथ खाएंगे ये फल और सब्जियां तभी मिलेंगे ये फायदे

स्वस्थ रहने के लिए ताजे फलों और हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। रोजाना अपनी डाइट में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करने से हमारा शरीर हैल्दी और रोग मुक्त रहता है। मगर ज्यादातर लोग इनके छिलके उतार देते हैं। जिन छिलकों को हम कचरा समझ कर फेंक देते हैं उनमें कई सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। आज हम आपको ऐसे फलों और सब्जियों के बारे में बताते हैं जिन्हें छिलके समेत खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं।

1. आम
जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए आम का छिलका बहुत फायदेमंद है जबकि आम के पल्प में वैसा कोई असर नहीं होता। इसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 औ 6 एसिड से भरपूर होता है। इसलिए आम के छिलकों को फेंके नहीं बल्कि खाएं।

2. चीकू
चीकू में नैचुरल मिठास और पौषक तत्व होते हैं। इसके आलावा इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई की भरपूर मात्रा होती है। बिना छिले चीकू खाने से हमें कई फायदे होते हैं।

3. सेब
ज्यादातर लोग सेब के छिलके उतार कर खाते हैं जो कि गलत है। इसके छिलको में घुलनशील फाइबर होते हैं जो शरीर में पाए जाने वाले बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेबल को कम करने में मदद करता है।

4. अंगूर
आपको जानकर हैरानी होगी की कुछ लोग अंगूर के भी छिलके उतार कर खाते हैं। इनके छिलके में resveratrol होता है दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।

इन सब्जियों को खाएं छिलके समेत

5. आलू
आलू के छिलके में इसके पल्प से लगभग 7 गुना ज्यादा कैल्शियम और 17 गुना आयरन होता है। जब आप आलू के छिलके निकाल देते हैं तो इसके 90% तक न्यूट्रिएंट्स और फाइबर कम हो जाते हैं।

6. गाजर
गाजर के छिलको में बीटा कैरोटिन होता है जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही छिलके समेत गाजर खाने से स्किन पर तेज धूप का कोई नहीं होता।

7. खीरा
हम बड़े चाव से खीरे का छिलका उतार कर खाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं? इसके छिलके में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी होता है। छिलके समेत खीरा खाने से हमें हैल्दी रहते हैं।

वजन तेजी से होगा कम अगर रोजाना 2 चम्मच खाएंगे यह एक चीज

मलाई खाने के फायदे : मलाई खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मगर कई लोग सोचते हैं कि मलाई खाने से फैट बढ़ता है, जोकि गलत है। रोजाना मलाई का सेवन आपका वजन तेजी से कम करता है न की बढ़ाता है। दरअसल, मलाई में प्रोटीन और गुड फैट होता है, जिसके कारण वजन बढ़ने नहीं बल्कि कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि किस तरह मलाई के सेवन से आप वजन कम कर सकते हैं।

कब और कितनी मात्रा में खाएं मलाई?

मलाई से गुड फैट और गुड केलेस्ट्रॉल दोनों ही मिलता है। इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी नहीं होती। मगर मलाई सही समय और लिमिट मात्रा में ही खानी चाहिए। हर किसी को रोजाना 2 चम्मच मलाई का सेवन सुबह या दोपहर के समय करना चाहिए। रात को सोने से पहले इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। दरअसल, मलाई में प्रोटीन होता है। रात में प्रोटीन को पचाना मुशिकल होता है क्योंकि उस वक्त बॉडी ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। ऐसे में मलाई हमेशा सुबह या दोपहर के समय सिर्फ 2 चम्मच ही खाएं।

क्यों फायदेमंद है मलाई
मलाई में लैक्टिक फर्मेन्टेशन प्रोबायोटिक होता है, जिससे आंतों की सेहत अच्छी बनी रहती है। इतना ही नहीं, मलाई का सेवन बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। रोजाना 2 चम्मच मलाई खाने से आप घुटनों में दर्द की समस्या से भी बचे रहते हैं। मगर किडनी की समस्या होने पर मलाई का सेवन कम ही करना चाहिए क्योंकि मलाई खाने से शरीर में यूरिक एसिड बहुत बनता है।

वजन नहीं बढ़ता
एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना मलाई खाने से वजन नहीं बढ़ता बल्कि कम होता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले और बाद में एक चम्मच मलाई जरूर खाएं। इससे वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वर्कआउट करने से जो प्रोटीन लॉस होता है उसकी भरपाई भी मलाई खाने से हो जाती है।

इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत
मलाई में विटामिन ए और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहता है। इससे आप जल्दी बीमार नहीं होते और कई गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा मलाई खाने से शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को भी मजबूत करता है।

मोटापे से लेकर डायबिटीज तक, हर बीमारी का काल है यह आयुर्वेदिक पानी

मेथी के दाने सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ज्यादातर लोग मेथी का सेवन सिर्फ सब्जी में छौंक लगाने के लिए करते हैं जबकि मेथी का पानी और भी ज्यादा गुणकारी है और यह आपको कई बीमारियों से बचाता है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू कर दें तो समझिए कि अगले कुछ ही दिनों में पेट से जुड़ी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

ऐसे बनाएं मेथी का पानी

मेथी का पानी बनाने के लिए एक से डेढ़ चम्मच मेथी दानों को रात में एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को अच्छे से छान लें और फिर इसे खाली पेट ही पिएं।

मेथी के पानी के फायदे

1. सर्दी-जुकाम से राहत
मेथी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसी वजह से मेथी का पानी सर्दी-जुकाम या वायरल से बचाने में बहुत सहायक है। मेथी का पानी शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है और संक्रामक रोगों से आपको बचाता है।

2. डायबिटीज को नियंत्रित करने में मददगार
मेथी में मौजूद गेलेक्टोमैनन नामक फाइबर खून में शूगर के अवशोषण को कम करता है। इससे शरीर का ब्लड शूगर लेवल नियंत्रित रहता है और डायबिटीज से बचाव होता है।

3. एसिडिटी में रामबाण
जिन लोगों को एसिडिटी या गैस की समस्या है उनके लिए मेथी का पानी रामबाण इलाज है। रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास मेथी का पानी पीने से पेट की जलन दूर होती है और अपच या एसिडिटी से तुरंत आराम मिलता है।

4. किडनी की पथरी से आराम
इसके नियमित सेवन से किडनी की पथरी में आराम मिलता है। मेथी में मौजूद तत्व पथरी को गलाने में अहम भूमिका निभाते हैं हालांकि पथरी दूर करने का यह सिर्फ एक घरेलू उपाय है। इसके अलावा डॉक्टर की मदद जरूर लें।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

‘हमारे बारह’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की ‘सुप्रीम’ फटकार

फिल्म हमारे बारह पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। विवादों में घिरी इस फिल्म के मेकर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेकर्स द्वारा इस फिल्म के 2 डायलॉग को हटाने पर सहमति जताने के बाद इसकी रिलीज की अनुमति दे दी थी। कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाएगी और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अन्नू कपूर की फिल्म हमारे बारह की रिलीज पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा मामले की सुनवाई और निपटारा नहीं हो जाता, तब तक यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, हमने सुबह फिल्म का टीजर देखा और यह बेहद आपत्तिजनक है। बात दें कि हमारे बारह पहले 7 जून और फिर 14 जून को रिलीज होनी थी। ऐसे में याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें फिल्म को दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ट्रेलर इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है।

G. D. JALAN COLLEGE
Estd. : 2011
Affiliated to University of Mumbai & M.S. Board (MARWARI MINORITY)
Upper Govind Nagar, Malad (East)
NAAC accredited with B+ ISO 9001: 2015 Certified College
Admissions Open
The following programs are as per National Education Policy (NEP 2020)
B.Com.: : Bachelor of Commerce
B.Com.: : Bachelor of Commerce (Management Studies)
B.A.F.: : Bachelor of Commerce (Accounting and Finance)
B.Sc.: : Bachelor of Science
B.Sc.I.T.: : Bachelor of Science (Information Technology)
College Code : MU-0527
Contact Number: 9321558419/ 9321674124